स्टॉक लिमिट पूरी नहीं कर सकेंगी चीनी मिलें, प्राइस घटना मुश्किल

जयश्री भोसले | पुणे

अब यह लगभग तय हो गया है कि महाराष्ट्र की चीनी मिलें केंद्र सरकार के निर्देश के मुताबिक कीमतों पर नियंत्रण के लिए अपने स्टॉक को प्रॉडक्शन के 37 पर्सेंट तक कम नहीं कर पाएंगी।

महाराष्ट्र एफडीए ने चीनी मिलों को स्टॉक में कमी करने के लिए मनाना शुरू कर दिया है, लेकिन इंडस्ट्री का कहना है कि उसके लिए एक सप्ताह में इतनी बड़ी मात्रा में स्टॉक को कम करना संभव नहीं है। अगर मिलें स्टॉक नहीं घटातीं तो चीनी की कीमतों पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा।

केंद्र सरकार ने आठ सितंबर को एक निर्देश के जरिए मिलों को सितंबर के अंत तक अपने स्टॉक का केवल 37 पर्सेंट और अक्टूबर के अंत तक 24 पर्सेंट रखने की अनुमति दी थी। इसके बाद महाराष्ट्र की मिलों ने बड़े पैमाने पर बिक्री की है।

हालांकि, इससे कीमतों में मामूली कमी ही आई है। NCDEX पर वाशी डिलीवरी के लिए चीनी के स्पॉट प्राइसेज एक सितंबर को 36.35 रुपये प्रति किलोग्राम और 22 सितंबर को 36.45 रुपये प्रति किलोग्राम थी।

स्टॉक घटाने की समयसीमा में केवल आठ दिन बचे होने की वजह से इंडस्ट्री का कहना है कि यह लक्ष्य पूरा नहीं किया जा सकता। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव शुगर फैक्टरीज फेडरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर संजीव बाबर ने कहा, 'चीनी मिलों को दी गई समयसीमा अधिक होनी चाहिए थी।'

इंडस्ट्री ने हाथ खड़े किए

- **महाराष्ट्र एफडीए** ने चीनी मिलों को स्टॉक में कमी करने के लिए मनाना शुरू कर दिया है, लेकिन इंडस्ट्री का कहना है कि उसके लिए एक सप्ताह में इतनी बड़ी मात्रा में स्टॉक को कम करना संभव नहीं है
- **केंद्र सरकार** ने आठ सितंबर को एक निर्देश के जरिए मिलों को सितंबर के अंत तक अपने स्टॉक का केवल 37 पर्सेंट और अक्टूबर के अंत तक 24 पर्सेंट रखने की अनुमति दी थी

राज्य की एक बड़े शुगर कोऑपरेटिव के मैनेजिंग डायरेक्टर ने बताया, 'आमतौर पर हम हर महीने अपने प्रॉडक्शन का 7-8 पर्सेंट बेचते हैं। अक्टूबर के लिए सरकार ने हमारे स्टॉक का जो टारगेट तय किया है, वह पूरा करना संभव नहीं है।' सरकारी सूत्रों ने बताया कि राज्य में अभी भी 40 चीनी मिलें ऐसी हैं, जिनके पास चीनी का 37 पर्सेंट से अधिक स्टॉक है। महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (एफडीए) के कमिश्नर महेश पाठक ने कहा कि आठ सितंबर के केंद्र सरकार के ऑर्डर से पहले उनके डिपार्टमेंट ने चीनी मिलों को चीनी बेचने के लिए मनाना शुरू कर दिया था। उन्होंने बताया, 'हम पिछले तीन महीनों से मिलों पर चीनी बेचने के लिए दबाव बना रहे हैं। हमारा अनुमान है कि सितंबर में मिलों को 10 लाख टन चीनी बेचनी चाहिए।' राज्य के एक चीनी मिल मालिक ने कहा, 'सरकारी अधिकारियों को भी यह नहीं पता कि क्या करना है। अगर वे चीनी को जब्त करते हैं तो हम कोटा को बरकरार नहीं रख सकेंगे। इससे सरकार भी इसकी बिक्री नहीं कर पाएगी।'

हालांकि, उत्तर प्रदेश की अधिकतर चीनी मिलों ने पहले ही अपने स्टॉक का केवल 37 पर्सेंट रखने का टारगेट पूरा कर लिया है क्योंकि वे चीनी के दाम बढ़ने के बाद से लगातार बिक्री कर रही थी।